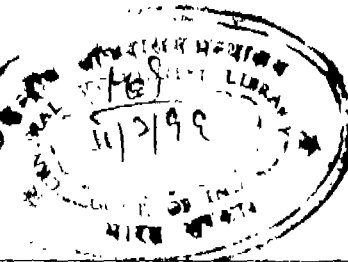


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 753]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 23, 1998/अग्रहायण 2, 1920

No. 753]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 23, 1998/AGRAHAYANA 2, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1998

का. आ. 988(अ).—बोडो सिक्युरिटी फोर्स जिसका परिवर्तित नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड है (जिसे इसमें पश्चात एन. डी.एफ.बी. कहा गया है) का पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथक्तावादी संगठनों से मिलकर, बोडोलैंड को मुक्त कराना, जिसके परिणामस्वरूप उक्त क्षेत्र भारत संघ से अलग हो जाए और भारत-बर्मा क्षेत्र की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए, उस क्षेत्र के समधि संगठनों से मिलकर संघर्ष जारी रखना और उससे बोडोलैंड को भारत से अलग कराना प्रवर्जित उद्देश्य हैं,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि एन.डी.एफ.बी.:—

- (i) पृथक बोडोलैंड स्थापित करने के अपने उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, भारत की प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को विच्छिन्न करने वाले या के लिए आशयित अनेक अवैध और हिंसात्मक क्रिया कलापों में लिप्त रहा है,
- (ii) पृथक बोडोलैंड के सृजन के लिए अन्य विधि-विरुद्ध संगमों, जैसे युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (यू.एल.एफ.ए.) और नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (एन.एस.सी.एन.), के साथ संबद्ध रहा है,
- (iii) उस अवधि के दौरान भी जब इसे विधि-विरुद्ध संगम घोषित किया गया था, यह अपने ध्येय और उद्देश्य के अनुसरण में कई हिंसक और विधि-विरुद्ध क्रियाकलापों में लगा हुआ था जिससे कि उसने सरकार के प्राधिकार को जर्जरित किया है और जनता में आतंक और संत्रास फैलाया है,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि हिंसक क्रियाकलापों में निम्नलिखित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं:—

- (i) 23-11-96 से 19-8-98 की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसक और आतंकवादी घटनाएं हुईं जिनमें 237 हत्याएं भी सम्मिलित हैं, जो एन.डी.एफ.बी. द्वारा की गई मानी जा सकती हैं,
- (ii) पृथक बोडोलैंड के सृजन के लिए वित्त पोषण और योजनाओं के निष्पादन की दृष्टि से फिरौती के लिए अपहरण के कार्यों के अतिरिक्त व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सिविलियनों से निधियों का उद्घापन करना,
- (iii) उसकी आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए, नए कैडरों की भर्ती और जिला, आंचलिक और शाखा समितियों के पुनर्गठन के लिए व्यवस्थित अभियान चलाना,
- (iv) इकाई के उद्देश्य को विशिष्टता देने वाली तथा केन्द्रीय सरकार पर शोषण का आरोप लगाने वाली और लोगों को तथाकथित मुक्ति संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित करने वाली और इस प्रकार उन्हें निष्ठा-विमुख करने वाली गुप्त पत्रिका प्रकाशित करना,
- (v) अपने काइरों को पुलिस भेदियों/सरकार के सहयोगियों की सूची तैयार करने के लिए हिंदायत देना जिससे उनके विरुद्ध प्रतिकरात्मक कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य की पहचान की जा सके,
- (vi) गैर बोडो में संत्रास और असुरक्षा फैलाने और उन्हें बोडो क्षेत्र से प्रजनन के लिए मजबूर करने की दृष्टि से हत्याकाण्ड और जातीय हिंसा फैलाना, जिसके परिणामस्वरूप हत्याएं, संपत्ति का विध्वंस और हजारों गैर बोडो का कोकराझाड़, बागईगांओं और बरपेटा जिलों में स्थित उनकी रोजी-रोटी और घरों से निर्गमन हुआ,

(vii) इसके पृथकतावादी क्रियाकलापों को चलाने के लिए देश की सीमा से पार कैम्पों और छिपने के ठिकानों की स्थापना करना,

(viii) पृथक बोडोलैण्ड के सृजन के लिए उनके संघर्ष में शस्त्र और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में भारत-विरोधी शक्तियों की सहायता लेना, आदि।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि पूर्वोक्त कारणों से, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड के क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं और यह एक विधिविरुद्ध संगम है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है,

और, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड के विधिविरुद्ध क्रियाकलाप, संगठन के क्रियाकलाप नियंत्रणाधीन नहीं रखे जाते हैं, तो संगठन पुनः समूहित हो सकता है और पुनः स्वयं को शस्त्र से सज्जित रख सकता है, नई भर्तियाँ कर सकता है, हिंसा, आतंकवादी और पृथकतावादी क्रियाकलापों में लग सकता है, निधि आदि का संचय कर सकता है और निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों के जीवन को संकटापन्न कर सकता है और इसलिए ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड को तात्कालिक प्रभाव से, विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक हो जाता है,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर उल्लिखित नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, और हाल ही में विगत काल में पुलिस, संशस्त्र बलों और नागरिकों के विरुद्ध इस इकाई द्वारा बढ़ाई जा रही हिंसा का सामना करने के लिए तात्कालिक प्रभाव से, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैण्ड को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है और तदनुसार केन्द्रीय सरकार, उस धारा की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जा सकेगा, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 11011/68/98-एन. ई.-IV]

डा. पी. डी. शेनोयें, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 1998

S.O. 988(E).—Whereas the Bodo Security Force since rechristened as National Democratic Front of Bodoland (hereinafter referred to as NDFB) has as its professed aim, the "Liberation" of Bodoland resulting in bringing about the secession of said areas from the Indian Union, in alliance with other armed secessionist organisation of the North East region and to carry on struggle for the national liberation of the Indo-Burma region in alliance with like-minded organisations of that region and thereby, the secession of Bodoland from India ;

And whereas the Central Government is of the opinion that NDFB has—

- (i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt or which disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland ;
- (ii) aligned itself with other unlawful associations like United Liberation Front of Asom (ULFA) and National Socialist Council of Nagaland (NSCN) to create a separate Bodoland ;
- (iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the period when it had been declared as an unlawful association, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and panic among the people ;

And whereas the Central Government is further of the opinion that the violent activities include :—

- (i) large scale violent and terrorist incidents including 237 killings are attributed to NDFB during the period from 23-11-96 to 19-8-98 ;
- (ii) indulging in extortions of money from businessmen, government officials and other civilians in addition to acts of kidnapping for ransom with a view to finance and execute plans for creation of a separate Bodoland ;
- (iii) embarking on a systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district, anchalik and sakha committees, while continuing its terrorist and insurgency activities ;
- (iv) publishing clandestine magazines highlighting the goal of the outfit and alleging exploitation by the Central Government and inciting the people to join the so-called liberation struggle thereby subverting their loyalties ;
- (v) instructing its cadres to compile the list of police informers/government collaborators to identify targets for retaliatory action against them ;
- (vi) carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property and exodus of thousands of non-Bodos from their hearths and homes in Kokrajhar, Bongaigaon and Barpeta districts with a view to spread panic and insecurity among non-Bodos and forcing them to migrate from Bodo areas ;
- (vii) establishing camps and hideouts across the country's border to carry out its secessionist activities ;
- (viii) obtaining assistance from anti-India forces in other countries to procure arms and other assistance in their struggle for creation of a separate Bodoland etc.

And whereas the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the activities of NDFB are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the National Democratic Front of Bodoland to be an unlawful association ;

And whereas the Central Government is also of the opinion that, unless the unlawful activities of the NDFB are kept under control the organisation may re-group and re-arm itself, make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds etc. and endanger lives of innocent citizens and security forces personnel and the circumstances therefore do exist which

render it necessary to declare NDFB as an unlawful association with immediate effect ;

And whereas the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of NDFB mentioned above and to meet the sustained and ever increasing violence committed by this outfit in the recent past against the police, the armed forces and the civilians, it is necessary to declare NDFB to be an unlawful association with immediate effect and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of that section, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/68/98-NE. IV]

DR. P. D. SHENOY, Addl. Secy.

